

c
m
y

अधिकारी रीतेश अग्रवाल ने जानकारी दी कि जिले के 60 हजार से अधिक मजदूर प्रवासी हैं, जिनमें से 40 हजार लोगों के लौटने की सभाना का देयता हुए रीतेश की गई है। इनमें लाने के लिए ट्रेन के अलावा बसों की व्यवस्था भी की गई है। ट्रेन से आने वाले प्रवासी मजदूरों का स्टेशन पर तथा बसों से आने वाले मजदूरों का बहतराई स्टेशन में स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें बसों से क्वारंटीन स्टेशन भेजा जायेगा। इनके लिए 1066 सेंटर बनाये गये हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। प्रत्येक क्वारंटीन सेंटर के लिए कमचारियों की इयुटी निर्धारित की जा चुकी है।

राजधानीवादी अर्थशास्त्रियों का विचार था कि शहरीकरण के निरंतरण यातायात की टीम द्वारा अग्रिम अभियान चलाना शहर के बाहरी क्षेत्र में सड़क थ्रीड, ट्रांसपोर्ट नगर एवं मोहाना जिले के पास यातायात चर्चिका पैदा होना चाहिए। यातायात की टीम ने तीन सप्ताह के अभियान चलाते जाते मोटर साइकल, बिना चालू यातायात करने वाले 74 मोटर साइकल चालकों को चेक किया गया। अग्रिम चालक चालकों के लिए मोटर साइकल अर्थशास्त्रियों 1989 के तहत कार्यालय बिल 7 प्रकरण में कुल 14,800/- समझे शुल्क समूल किया गया। यह कार्यालय चालक निरंतर जारी रहे। अग्रिम अभियान यातायात नियमों के अनुसार-जैसे सफाई में दो से अधिक बेजान पर, तेजगति से चलाने वाले, जाहान चलाने चालक समग्र मोहाना जिले का उपयोग करने वाले चालकों के विरुद्ध भी कार्यालय सफाई चालक जाहान।

काम को पूरा कर लिया जा
जिससे यहाँ के लोगों को इस
लाभ मिलना शुरू हो जाए।

स्वतंत्राधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक यशवंत धोटे द्वारा ससल स्कूल केम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डी से मुद्रित कर कुबेर प्लाजा शॉप नं. 226 सेकंड फ्लोर लिंक रोड बिलासपुर से प्रकाशित, संपादक- रविशंकर शुक्ला
RNI NO.CHHHIN/2015/62431, डाक पंजीयन क्रमांक जी 2-112/सी जी/बी.एल.पी./108/2020-2022, email: navpradesh@gmail.com, फोन व फैक्स : 07752-400878

बातों...बातों में...

सुकांत राजपूत

ताली बजवाए, पैसा तो दें...

कोरोना कोविड-19 से जंग के लिए केंद्र और राज्यों के बीच



अपनी पीठ थपथपाने की हंस्टेज सिटी के रूप में विकसित करने की तैयारी है। सिरपुर में विकास के लिए 56 करोड़ 15 लाख रुपए का प्रस्ताव बनाया गया है। विधायक विनोद सेनलाल चंदाकर की पहल व प्रयास से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने इसके लिए खाका तैयार किया है। विधायक श्री चंदाकर ने बताया कि सिरपुर के विकास के लिए राज्य शासन ने विशेष क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया है। इसके माध्यम से सिरपुर और आसपास के क्षेत्र को पुरातात्विक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने सिरपुर को हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। करीब 56 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों के लिए खाका तैयार किया गया है। नेशनल ह्यूडि 53 के पास सिरपुर

दाऊ इसलिए मांग रहे पैसा...

विश्व बैंक से 75 अरब रुपये कोविड 19 से लड़ने के लिए



अब तक विचार ही कर रहा है। खासकर छत्तीसगढ़ राज्य को तो कोविड-19 से लड़ने के लिए कोई आर्थिक मदद अब तक नहीं की गई है। चाईना का पैंड टेस्ट की खुद हवा निकल गई। कोरिया की फिट से जांच हुई जिसे खरीदा पड़ा है। विश्व बैंक से मिली मदद के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 30 हजार करोड़ के लिए दो बार पत्र भी लिख चुके हैं। लेकिन केंद्र सरकार है कि कान में पूं नहीं गिर रही।

पीएम केयर फंड भी लबरेज...

बात कर तो कोरोना संक्रमण के लिए पीएम केयर फंड में



केयर फंड और विश्व बैंक से मिले पैसे का ग्राहिसन-फिक्क वॉलिटेशन पोस्ट की सुविधा भी बनी। बलजुद इसके फंड और विश्व बैंक की राशि का कोरोना से जंग में कहा, किताब और अब विश्व बैंक को दिया गया यह जवाब फिलहाल पछता नहीं है। बातों ही बातों में आर्थिक गणिताओं का कानून है कि इन परिणामों का उपयोग कहीं आर्थिक लॉकडाउन से उबरने के लिए केंद्र न करे।

लोन का यह खामियाजा...

अब तक कोरोना से जंग का मतलब भारत में ताली, धावी,



यह विचार में पड़ गई। कोरिया से मंगवाई गई फिट से जांच रिपोर्ट में वज्र लाम। अब विश्व बैंक से जितनी लोन मिली कोविड-19 से निपटने के लिए राशि का उपयोग भले ही केंद्र सरकार अपने तरीकों से करे। परंतु वह तो साफ हो गया है कि अब इस लोन के एवज में भारत सरकार को डब्ल्यूएचओ की शर्त मानने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। क्योंकि जिन कारणों के लिए मदद मिली है उसके बाद निम्नलिखित डब्ल्यूएचओ के मुनाफिक ही लॉक डाउन पालन के अलावा पड़े गए टारक्स पर ही काम करना होगा। इसी का नतीजा है कि राज्य के मुनाफिक जांच शुरू होने के बाद ही सस की संख्या और मरने वाली की तादात प्रेश में बढ़ गई है। मतलब पहले जो था वह सिर्फ ताली, धावी के मुनाफिक चल रहा था।

राज्य का हिस्सा वाजिब है...

डब्ल्यूएचओ की गैरहा लाने को फंसील करना ही पड़ेगा।

लॉक डाउन की मिलाव, जांच के तरीके, निष्पक्षिता को राशन से लेकर दवाय तक उपलब्ध करवाने का निश्च मानन के लिए सरकार की बाधाता है। राज्यों को भी कोरोना से निपटने के लिए विश्व आर्थिक मदद के केंद्र सिर्फ गाइड लाइन फॉलो करना रहा है। मने में उन पैसों में राज्यों का भी हक बताया है। संक्रमणजन्य में शराब बिक्री भी रोकना गाइड लाइन के बाद ही राज्यों में शुरू हुई है। इतना ही नहीं केंद्र को युद्ध से भी बचने में जांच किट मुफ्त में मिलनी है जिसे वो उपयोग में ला रहा है। इस तरह हिस्से लोने में फिक्करी वाली कहनायत केंद्र सरकार की है। अर्थात् एकरा बाहरी मदद, देवासिर्गणों का केयर फंड में करोड़ों रुपए का दान अब मुफ्त में दे के खोखे व्यंग भेजी गई जांच किट के अलावा सेंट्रल के खार्ड भंडारण में अन्न का भार स्टॉक भी है। फिर भी राज्यों को न तो आर्थिक मदद, मुफ्त अन्नान और जांच किट की सुविधा नहीं देता क्या सिरसर है?

हेरिटेज सिटी के रूप में सिरपुर को विकसित करने की तैयारी

सिरपुर में विकास के लिए 56 करोड़ का प्रस्ताव तैयार

नव प्रदेश संवाददाता

महासमुंद। पुरातात्विक व ऐतिहासिक नगरी सिरपुर को हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित करने की तैयारी है। सिरपुर में विकास के लिए 56 करोड़ 15 लाख रुपए का प्रस्ताव बनाया गया है। विधायक विनोद सेनलाल चंदाकर की पहल व प्रयास से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने इसके लिए खाका तैयार किया है। विधायक श्री चंदाकर ने बताया कि सिरपुर के विकास के लिए राज्य शासन ने विशेष क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया है। इसके माध्यम से सिरपुर और आसपास के क्षेत्र को पुरातात्विक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने सिरपुर को हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। करीब 56 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों के लिए खाका तैयार किया गया है। नेशनल ह्यूडि 53 के पास सिरपुर



विधायक की पहल पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने तैयार किया खाका

मार्ग में डेढ़ करोड़ की लागत से भव्य गेट व प्रवेश द्वार के निर्माण के साथ ही सर्वसुविधायुक्त म्यूजियम व प्रदर्शन सेंटर, सर्वसुविधायुक्त कैफेरिया का निर्माण प्रस्तावित है। तीन फेज में यह कार्य पूरा करने की तैयारी है। पहले फेज में 19 करोड़ 35 लाख की लागत से सिरपुर के ओवरऑल साइट में पॉलिंग प्लाज, स्मॉकम मॉडर के पास पार्किंग एरिया, इंटरनेशनल साइट, लैंडस्कोप कोर्ट व सेंटर, ओवरऑल साइट में लाइटिंग

प्रमुख सचिव सहित अफसरों ने लिया जायजा

सिरपुर को हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित करने छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव आरपी मंडल सहित अफसरों की टीम ने शनिवार को सिरपुर पहुंचकर आसपास जानकारी ली। इस दौरान मौजूद विधायक श्री चंदाकर ने छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रोजेक्ट की ओर अफसरों का ध्यानकषित कराया। साथ ही गंधेशनाथ मंदिर के पास महानदी तट पर तटबंध निर्माण, वाफिग स्ट्रीट व रायकरेता तालाब सौंदर्यीकरण कराए जाने पर ज्ञात दिया। जिस पर सीएस श्री मंडल ने कहा कि आने वाले दिनों में इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने रेस्ट हाउस के सामने स्मारिका के आसपास अतिरिक्त को अन्यत्र शिप्ट करने के निर्देश दिए। इस दौरान सचिव टूरिज्म अंबलगत पी, पीसीसीएफराकेश चतुर्वेदी, कलेक्टर सुनील जैन, एसपी प्रफुल्ल जाकुर, डीएफओ मयंक पांडे आदि मौजूद थे।

सौरदीकरण, पार्किंग आदि का निर्माण कराया जाना है। वहीं तीसरे फेज के लिए 13 करोड़ 14 लाख की कार्ययोजना तैयार की गई है। जिसके तहत ओवरऑल साइट में मीटर ट्रायल, सर्वसुविधायुक्त म्यूजियम का

निर्माण किया जाना है। गौरतलब है कि सिरपुर विकास पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विधायक श्री चंदाकर ने विकास की ओर ध्यानकषित कराया था। जिसके बाद इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है।

गरीब जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा पीएम आवास योजना का लाभ

नव प्रदेश संवाददाता

लवन। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी और गरीब जरूरतमंदों के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अंचल के वास्तविक गरीब जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है शासन के अनुसार 2011 के सर्वे अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना है। प्रधानमंत्री आवास योजना से हजारों घर बने हैं और हितग्राही लाभान्वित हुए हैं लेकिन वर्ष 2011 की छेड़कर भी बकौदबनजार विकासखंड क्षेत्र में ऐसे कई गरीब परिवार हैं जिन्हें शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही एक परिवार जनपद पंचायत बलीदा बजार



को मजबूर है। दिनभर रोजी मजदूरी करके करने के बाद घर पर आराम करने का पथीय स्थान नहीं है। इस दृष्टि से वे प्रथम मंत्री आवास योजना लिए पात्र हितग्राही होना चाहिए किंतु उन्हें अब तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। पीएम आवास के लिए पूर्व विधायकसाधु आथख गरीशंकर अग्रवाल विधायक शकुंतला साहू जिला कलेक्टर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और ग्राम पंचायत में कई बार आवेदन देने के बावजूद वर्ष 2011 के सर्वे सूची में नाम नहीं होने के कारण

इस संबंध में सेक्टर गम रखने के बताया कि 2011 में सर्वे हुआ था उस समय इस मंत्री घर में ताला लगाकर जीने खाते



लॉकडाउन में नियमों का पालन करते हुए की गई शादी

नव प्रदेश संवाददाता

लवन। देशभर में कोरोना का कहर है। जहां कुछ लोग मनमानी करते हुए लाक डाउन की धमियां उड़ा रहे हैं तो वहीं समझदार लोग लॉक डाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला बलीदा बजार विकासखंड के ग्राम लुवड़ा का सामने आया है जहां लॉक डाउन के लिए दी गई शर्तों के साथ शादी करते हुए नव दंपति सदा फेंगों के साथ विवाह के बंधन में बंधे।

लुवड़ा निवासी नंदू रजक की बहू लड़की गजु रजक की शादी पेंड्री सुहेला निवासी रौहित

निर्मलकर के पुत्र शनवार अर्नलकर के साथ 2 अर्नल को तय हुई थी किंतु लॉक डाउन के कारण शादी नहीं हो पाई। लॉक डाउन 3 में नियम और शर्तों के साथ शादी के लिए दी गई शर्त के बाद जिला कार्यलय से आदेश लेकर गत दिनों वर पक्ष से 5 लोग और वधू पक्ष से 5 लोग ग्राम गावकार में रजक समज के ग्राम जानकी मंदिर में उषाधिया होकर लॉक डाउन का पालन करते हुए हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की। पूरी रस्म पूरी की गई। विवाहदि जोड़े ने कहा कि हम लोगों ने लॉक डाउन का पालन करते हुए शादी की है यह भी जीवन में एक पेंड्री सुहेला निवासी रौहित फावना बनी रंगी।

बिना मां के बच्चों को बिलखता देख भावुक हुई विधायक, पिता को लाने भेजा बस

नव प्रदेश संवाददाता

बिलासपुर। कोरोना के इस काल ने अच्छे अच्छे लोगों की परीक्षा ले लिया है। यह सच है कि सरकार अपने नागरिकों को लगातार महजुब रखने का प्रयास कर रही है। लेकिन यह भी सच है कि कोरोना काल में लोग बहुत निग्रो हो रहे चले हैं। बाहर से आने वाले परिवार के सदस्यों के प्रति लोगों में बहुत अधिक उत्साह नजर नहीं आ रहा है। बावजूद इसके सरकार अपने को दृढ़ कर पर ला रही है। जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है

जैसा की सबको मालूम है कि आज के इस दिन को मर्दस डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन कोरोना और मौत के भय ने लोगों को तोड़कर रख दिया है। लोग किसी की आवाज सुनने को तैयार नहीं हैं। इस बीच रश्मि सिंह को जानकारी मिलती है कि बेलगाम क्षेत्र निवासी एक महिला सीता बाई की लाकडाउन के समय काल के दौरान रश्मि में मौत हो गई। उसके तीन बहू ही छोटे बच्चे हैं। जो इस रहस्यक अपने पिता और मां को याद करते हैं। तीनों की हालत बहुत खराब है

मानवता सबसे बड़ा धर्म... मैं भी मां हूं- रश्मि सिंह

तखतपुर रश्मि सिंह ने बताया कि देश के कोने कोने में फंसे सभी मजदूरी को सरकार परिवहन की व्यवस्था कर पर ला रही है। लेकिन इस मामले में तखतपुर और मरमा का है। कृष्ण मणि करमाकर सरकार के प्रयास से जरूर घर पहुंचता। लेकिन जब इस दौरान बच्चों की हालत बस से बदतर होती जा रही है। बच्चे अपने पिता को याद कर रहे हैं। पति बच्चों की मां के अतिरिक्त संसार में शामिल नहीं हो सका। करमाकर घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य है। ऐसी सूचना से उसे बच्चों के बीच रहना बहुत जरूरी है। बच्चों से मिलकर कलेजा छतनी हो गया है। इसलिए विशेष और निजी प्रयास से एक उस छिन्दाड़ा भेजी हूं। प्रयास किया जा रहा है कि बस से अन्य प्रवासी भी घर लौट आए।

चली है। पिता कृष्ण मणि कर्माकर होरांगवाड मध्यप्रदेश में रोजी मजदूरी का काम करता है। लाकडाउन के चलते पत्नी को आतिय संस्कार में भी शामिल नहीं हो सका। इस बीच कर्माकर की नौकरी भी लगी चली गई। और पति बच्चों से मिलने वह होरांगवाड से पैरल ही तखतपुर के लिए निपट पड़ा। इस दौरान उसके साथ तखतपुर के और भी मजदूर परिवार साथ हो लिए।

मामले को जानकारी तखतपुर विधायक रश्मि सिंह तक पहुंची। तत्काल अनाथ बच्चों से मिलने घर पहुंच गई। इस दौरान मासूम बच्चों को रोता बिखला देखा रश्मि सिंह टूट गई। उन्हें जानकारी मिली कि पीछे बच्चों के पिता शिखरादा में फंसे हैं। उसके साथ तखतपुर के अन्य कई मजदूर परिवार कई छोटे बच्चों के साथ लापता पैरल चल रहे हैं। ज्ञात हो कि बेलगाम क्षेत्र निवासी मजदूर परिवार का मुखिया कृष्ण मणि कर्माकर और दत्ता होरांगवाड स्थित एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं। गांव में कर्माकर की पत्नी सीता बाई घर का काम करने के अलावा नई बच्चों को पालन पोषण कर रही थी। लाकडाउन के दौरान सीता बाई की तबीयत बहुत खराब हो गयी। बिलासपुर स्थित रश्मि में

पत्नी कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी। मामले को जानकारी होरांगवाड में कृष्ण मणि कर्माकर तक पहुंची। लेकिन अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। इस बीच फैक्ट्री भी बन्द हो गयी। बेरोजगार हो चुका कर्माकर कुछ दिन इंतजार के बाद अपने साथियों के साथ बच्चों को याद कर पलट लौट तखतपुर के लिए निपट पड़ा। लेकिन छिट्छवाड़ा पहुंचने तक धैर्य ने जवाब दे दिया।

स्थानीय लोगों के प्रयास से वह छिट्छवाड़ा में रुका और लोगों के सहयोग से अपना सदर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल

तक पहुंचाया। बगते चले कि राज्यपाल अनुसूच्य जाके छिट्छवाड़ा की रहने वाली है। राज्यपाल ने सरकार को मामले से अवगत कराया। लेकिन इस बीच अन्य लोगों के प्रयास से जानकारी तखतपुर विधायक रश्मि सिंह तक पहुंची।

ठीक मर्दस डे के दिन रश्मि सिंह बच्चों से मिलने घर पहुंच गई। बच्चों को रोता बिखला देखा विधायक मां का कलेजा जार जार हो गया। उन्होंने मासूम बच्चों को बिखला देखा एक फैसला लिया जिसकी तत्काल उम्मीद लोगों को नहीं थी। वह जानते हुए भी सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरों को घर लाने का प्रयास सरकार कर रही है। बावजूद इसके उन्होंने निजी रूप से बच्चों के खातिर पितृ कृष्ण मणि कर्माकर को लेने एक बस छिट्छवाड़ा के लिए खाना कर दिया। रश्मि सिंह ने बताया कि बच्चों की मां का निधन हो गया है। हालात ऐसे हैं कि बिना पितृ के बच्चों की सेवा मुश्किल है। छिट्छवाड़ा पहुंचने के पितृ को लाने का व्यवस्था की गयी है। हमने यह भी प्रयास किया है कि जब बस जा रही है तो लाकडाउन में फंसे बिलासपुर के अपना मजदूर भी साथ आ जाए।



प्रथम खरीफ वर्ष में 80.37 लाख मीट्रिक टन तथा द्वितीय खरीफ वर्ष में 82.80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का कीर्तिमान

सर्वाधिक लगभग 19 लाख किसानों से धान खरीदी का कीर्तिमान

2500 रु. प्रति बिन्टल पर धान खरीदी का निभाया वादा

'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' के तहत किसानों को फसलों का उचित दाम एवं मेहनत का समुचित सम्मान दिलाने के लिए 5300 करोड़ रुपए का प्रावधान। यह राशि समर्थन मूल्य तथा 2500 रु. के मध्य अंतर की भरपाई करेगी।

17 लाख 5 हजार किसानों को 8 हजार 818 करोड़ रु. कृषि ऋण माफी

244.18 करोड़ रुपए की सिंचाई कर माफी

कृषि भूमि के विकास कार्यों के लिए अधिग्रहण की स्थिति में भूवायवा राशि दो से बढ़ाकर चारगुना

उद्योग लगाने के लिए अधिग्रहित कृषि भूमि का उपयोग नहीं होने पर तथा आदर्श पुनर्वास कानून का पालन नहीं करने पर लोहपट्टीगुडा में 1707 आदिवासी किसानों की 4200 एकड़ जमीन वापस।



- भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ है तैयार,
कोरोना की ही होगी हार



देशव्यापी लॉक डाउन में भी छत्तीसगढ़ का हौसला आप

छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों, कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देकर हर संकट से मुकाबले के लिए किया तैयार.....

- व्याज मुक्त कृषि ऋण वितरण भी राज्य के इतिहास में सर्वाधिक राशि तथा सर्वाधिक किसानों को लाभ, राज्य में कृषि ऋण वितरण पहली बार 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक
- 5 लाख से अधिक किसानों को पात्रता अनुसार निशुल्क एवं सस्ती बिजली प्रदाय का इंतजाम
- 22 लाख किसानों को 'किसान क्रेडिट कार्ड' जारी
- लॉक डाउन के दौरान फसल बीमा तथा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत राज्य शासन की विशेष पहल से 900 करोड़ रुपए किसानों के खातों में अंतरित
- कृषि विभाग द्वारा 'वॉटरशेड मिशन' के तहत कार्यों से 25 लाख मानव दिवस रोजगार के सृजन का इंतजाम
- जल संसाधन विभाग द्वारा निविदा वाले 250 करोड़ रुपए लागत के निर्माण कार्यों की शुरुआत
- छत्तीसगढ़ मण्डी अधिनियम तथा उपविधि के तहत जो किसान अपनी फसल कृषि उपज मण्डी प्रोग्राम तक विक्रय हेतु नहीं ला पाते, उसके लिए आपसी सौदा के आधार पर सीदा पत्रक से विक्रय की व्यवस्था
- लॉक डाउन के दौरान किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु जिलावार हेल्प लाइन नम्बर जारी
- फसल कटाई के दौरान फिजिकल दूरी बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी
- आगामी खरीफ फसलों के लिए 9.08 लाख बिन्टल बीज की मांग को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में अब-तक 1.70 लाख बिन्टल धान बीज तथा 755 बिन्टल सोयाबीन बीज का भण्डारण प्रक्रिया केंद्र एवं समितियों में कराया गया
- कृषि उत्पादों के राज्य में ही वेल्यूएडेशन के लिए पूरे राज्य में फूडपार्क की स्थापना हेतु विभिन्न कार्यों में प्रगति
- नई उद्योग नीति वर्ष 2019-24 में राज्य में उत्पादित हर फूल, सब्जी, हार्डवेयर, लघुउद्योग, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण, जैव ईंधन, इथेनॉल की रिफाइनरी जैसे कार्य नई उच्च प्राथमिकता श्रेणी में
- लॉक डाउन के दौरान कृषि तथा उद्योगिक उत्पादन के परिवहन हेतु कोविड स्पेशल मालगाड़ी की व्यवस्था
- किसान अपने उत्पाद सब्जी, फल, मछली, चिकन, अण्डा,

- अनाज एवं कृषि उत्पादों को विक्रय के लिए अन्य स्थानों में मालगाड़ी द्वारा भेजने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित मार्ग एवं समय की जानकारी प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर मोबाइल नंबर 9752475950 एवं चीफ कमर्शियल मैनेजर मोबाइल 9752475903 दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अलावा परिवहन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए दक्षिणी-पूर्वी मध्य रेलवे के हेल्प लाइन नम्बर 138 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। परिवहन में लगने वाले राशि की गणना दूरी एवं वजन के अनुसार है
- कृषि विभाग द्वारा आगामी खरीफ सीजन में दलहन के रकबे में 28 फीसदी तथा तिलहन के रकबे में 33 फीसदी की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
- आगामी खरीफ सीजन में 37 लाख हेक्टेयर धान की बुआई का लक्ष्य है।
- मक्का के रकबे को 2 लाख 5 हजार हेक्टेयर से बढ़ाकर 2 लाख 38 हजार हेक्टेयर तथा अन्य अनाज की फसलों के रकबे को 76 हजार हेक्टेयर से बढ़ाकर 90 हजार हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। अरहर के रकबे में 34 हजार हेक्टेयर, उड़द के रकबे में 25 हजार हेक्टेयर, अन्य दलहनी के रकबे में 21 हजार हेक्टेयर की वृद्धि का लक्ष्य है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के 4 लाख 55 हजार 795 किसानों को 634 करोड़ 13 लाख 13 हजार रुपए का दावा भुगतान किया गया है। इस साल खरीफ सीजन में मौसम की खराबी, ओंधी-नुफान एवं ओलावृष्टि की वजह से खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा है। खरीफ फसलों के बीमा के एजेंट में किसानों को लगभग 350 करोड़ रुपए का दावा भुगतान होना संभावित है।
- अक्टूबर 6-4 के तहत प्रभावित कृषकों को अतिरिक्त राशि मिलेगी। खरीफ फसलों के दावा भुगतान की शुरुआत भी राज्य में की जा चुकी है। अब तक मुंगेली, कबीरधाम, बलरामपुर जिले के 2666 किसानों को 2.59 करोड़ रुपए का दावा भुगतान किया जा चुका है।

सुराजी ग्राम योजना के तहत, ग्रामीण संस्कृति और अर्थव्यवस्था को समवेत करते हुए हमने 'गरवा, घरवा, बारी' के जरिये अपनी चिन्हारी को बचाने का बीड़ा उठाया।

गरवा

2 हजार से अधिक जलाराधों के वैज्ञानिक ढंग से विकास का लक्ष्य है, जिसमें से 1207 नालों का डीपीआर तैयार।

घरवा

● 5 हजार गौठानों के विकास का लक्ष्य, 1905 गौठान निर्मित तथा 2700 चिन्हांकित। 1703 चारागाह निर्माण की स्वीकृति, 718 का कार्यपूर्ण।

● 5 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में गौठानों का विकास किया जा रहा है, जिसमें से प्रत्येक विकासखंड में एक 'मॉडल गौठान' बनाया जा रहा है।

● गौठानों में गोबर और मिट्टी का उपयोग सिर्फ जैविक खाद के लिए ही नहीं किया जा रहा है बल्कि दिए, मृत्तियां और हस्तकला के बेहतरीन नमूने भी इन गौठानों में बन रहे हैं। ये हस्तशिल्प हमारे शहरों में ही नहीं बल्कि महानगरों में भी बेचे जा रहे हैं।

घुरवा

● 4 हजार गांवों में 5 लाख टन से अधिक जैविक खाद तैयार तथा विक्रय।

● लगभग 3 लाख 14 हजार मीट्रिक टन जैविक खाद का निर्माण और उपयोग किया गया है। अब यह कार्यक्रम आंदोलन का रूप ले रहा

बारी

● 4500 गांवों में 1 लाख 45 हजार बारियों का उन्नयन।

● धान को बारिश से बचाने के लिए मनरेगा के माध्यम से चबूतरे तथा मंडी बोर्ड के माध्यम से शेड बनाने के निर्देश।

● मुख्यमंत्री की पहल पर लॉकडाउन के बाद अप्रैल माह में मनरेगा के कार्य व पुराने कार्यों को मिलाकर 548.41 करोड़ रु. का मजदूरी व सामग्री मद में 210 करोड़ रु. का भुगतान।

● 1.23 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन, 19.85 लाख श्रमिकों को रोजगार देने से बड़ी ग्रामीणों की कृय शक्ति।

रिजर्व बैंक ने सराहा-छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास

अपनी एक ताजा रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि लॉक डाउन के बावजूद, छत्तीसगढ़ राज्य में आर्थिक क्षेत्र में तेजी से वृद्धि देखी गई जो कि देश में सुखद वातावरण बनाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि, पिछले तीन हफ्तों में, घरेलू विकास पर कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं, लेकिन ये अर्थव्यवस्था की स्थिति में व्यापक भूलांछन करने के लिए बहुत निराश करते हैं। इन सबके बावजूद छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा, असम, कर्नाटक जैसे राज्य तालाबंदी के बावजूद वृद्धि गतिविधियों में अग्रणी हैं। खाद्यान्न और वायव्यानी के उत्पादन में, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के सभी कार्य में निरंतर तेजी बनी रहने के कारण इन राज्यों में देश के अन्य विकसित राज्यों के मुकाबले आर्थिक विकास की दर काफी अच्छी है।



किसानों के लिए जिलावार हेल्पलाइन

● रायपुर	: 1800-233-1850 रोल फ्री नं. 0771-2445785	● कोरवा	: 07759-221096
● बलौदाबाजार	: 07727-222054	● सरगुजा	: 1800-233-2637 रोल फ्री नं. 07714-222722
● गवियाबंद	: 07706-241288	● मुरझपुर	: 07775-266173
● महासमुंद	: 07723-223305	● बलरामपुर	: 1800-233-2663 रोल फ्री नं. 07831-273072
● धमशरी	: 07722-223458	● कोरिया	: 07836-232214
● दुर्ग	: 0788-2323755	● जरापुर	: 07763-220571
● बालोद	: 07749-223950	● जगदलपुर	: 07782-223122
● बेमरता	: 07824-222103	● कोणार्जोब	: 07786-242075
● राजनांदगांव	: 07744-224109	● देतेवाड़ा	: 07856-252360
● कबीरधाम	: 07741-232609	● बीजापुर	: 07853-220023
● बिलासपुर	: 07752-250084	● सुन्ना	: 07864-284012
● भुवेली	: 07755-264180	● नारायणपुर	: 07781-252214
● जांमशेरी-बांसा	: 07817-222215	● कांकेर	: 07868-241550
● रायगढ़	: 07762-223750	● गीरला-पेड़ा-मरावही	: 07751-220223

